सेंसेक्स की प्रमुख 10 में से पांच कंपनियों का मार्केट कैप 2.23 लाख करोड़ घटा

नई दिल्ली । बीते सप्ताह सेंसेक्स की प्रमुख 10 कंपनियों में से पांच के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में सामूहिक रूप से 2,23,660 करोड़ रुपये की गिरावट आई। शेयर बाजार में कमजोरी के रुख के बीच सबसे अधिक नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को उठाना पड़ा। सप्ताह के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार मूल्यांकन में गिरावट आई। वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, इन्फोसिस और आईटीसी की बाजार हैसियत बढ़ गई। समीक्षाधीन सप्ताह में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 81,763.35 करोड़ रुपये घटकर 19,19,595.15 करोड़ रुपये पर आ गया। सबसे अधिक नुकसान में रिलायंस इंडस्ट्रीज ही रही। एलआईसी का बाजार मूल्यांकन 63,629.48 करोड़ रुपये घटकर 5,84,967.41 करोड़ रुपये और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का 50,111.7 करोड़ रुपये घटकर 6,53,281.59 करोड़ रुपये रह गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बाजार हैसियत 21,792.46 करोड़ रुपये घटकर 5,46,961.35 करोड़ रुपये पर आ गई। आईसीआईसीआई बैंक का मूल्यांकन 6,363.11 करोड़ रुपये घटकर 7,57,218.19 करोड़ रुपये रह गया। इस रुख के` विपरीत टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 38,858.26 करोड़ रुपये बढ़कर 15,25,928.41 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। भारती एयरटेल का मूल्यांकन 11,976.74 करोड़ रुपये बढ़कर 6,89,425.18 करोड़ रुपये हो गया। आईटीसी की बाजार हैसियत 7,738.51 करोड़ रुपये बढ़कर 5,23,660.08 करोड़ रुपये पर और इन्फोसिस की 7,450.22 करोड़ रुपये के उछाल के साथ 6,78,571.56 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। एचडीएफसी बैंक का बाजार मूल्यांकन 4,443.9 करोड़ रुपये बढ़कर 11,03,151.78 करोड़ रुपये हो गया। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही। उसके बाद क्रमश= टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, एसबीआई, एलआईसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी का स्थान रहा।

जोमेटो को मिला 8.57 करोड़ का जीएसटी नोटिस

नई दिल्ली ।

खाना डिलिवरी करने वाली ऐप जोमैटो को 8 करोड़ रुपये से ज्यादा का जीएसटी ऑर्डर मिला है। ये नोटिस डेप्युटी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, गुजरात ने वित्त वर्ष 2018-19 से जुड़े टैक्स के बारे में जारी किया है। इस बारे में कंपनी मे शेयर बाजारों जानकारी देते हुए कहा कि इस जीएसटी ऑर्डर में कंपनी से 4 करोड़ से ज्यादा (4,11,68,604) रुपये के जीएसटी का भुगतान करने को कहा गया है। वहीं इस राशि पर ब्याज मिलाकर कुल अमाउंट 8,57,77,696 बनता है जो कि कंपनी को अदा करना है। इस नोटिस पर कंपनी ने कहा कि जोमैटो ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अपनी ओर से स्पष्टीकरण दिया था, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आदेश पारित करते समय अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से विचार नहीं किया गया था। ज़ोमैटो ने अपने बयान में कहा, वह उचित अधिकारियों के समक्ष इस आदेश को चुनौती देगी। वहीं दूसरी तरफ, एंटफिन सिंगापुर होल्डिंग ने 6 मार्च को ओपन मार्केट ट्रांसैक्शन के जरिए 2,827 करोड़ रुपये में ज़ोमैटो में अपनी दो प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी।एंटफिन सिंगापुर होल्डिंग पीटीई एंट फाइनेंशियल ग्रुप का सहयोगी है, जबकि एंट फाइनेंशियल ग्रुप चीनी ई-कॉमर्स दिग्गज अलीबाबा का हिस्सा है। इससे पहले ज़ोमैटो को 29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान अपने ग्राहकों से डिलीवरी शुल्क संग्रह पर ब्याज और जुर्माने के अलावा, दिसंबर 2023 में डिलीवरी शुल्क पर अवैतनिक जीएसटी के लिए ₹402 करोड़ का कारण बताओ नोटिस भी मिला था। कंपनी के शेयर की बात करें को शुक्रवार, 15 मार्च को बीएसई पर ज़ोमैटो के शेयर 4.68 प्रतिशत बढ़कर 9.90 पर बंद हुए।

चुनाव की घोषणा के साथ व्यापारियों को सताने लगा डर

कारोबारियों ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई, आचार संहिता के नाम पर कारोबार का नुकसान न हो

नई दिल्ली ।

चुनाव आयोग द्वारा चुनावी महाकुंभ की तारीखों का ऐलान करते ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता के नियम कायदों के चलते कई बार व्यापारियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। जिसके वजह से कारोबारियों ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि चुनाव आचार संहिता के नाम पर व्यापार और व्यापारियों का नुकसान न हो इसका ध्यान रखा जाए ताकि स्वतंत्र और निपष्क्ष चुनाव के साथ अर्थव्यवस्था की गाड़ी भी चलती रहे। चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद कारोबारी संगठन कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (केट) की तरफ से बयान जारी करके कहा गया कि देश में आम चुनाव होना 5 साल की एक प्रक्रिया है। व्यापार दिन-रात बारह महीने चलते रहता है। चुनाव में आचार संहिता लगाना अच्छी बात है। उतना ही जरूरी है कि व्यापार जिस तरीके से चलता है वह प्रभावित ना हो, चलता रहे। व्यापार में शहर के व्यापारी विभिन्न गांवों में, देहातों में, आदिवासी इलाकों की दुकानों में माल भेजते रहते हैं। समय-समय पर दौरा लगाकर अपने पैसे की वसूली करते हैं। काफी बड़ी रकम उनके पास जमा रहती है। इसी प्रकार सोना- चांदी के व्यापारी व अन्य सामानों के व्यापारी अपनी गाड़ियों में माल भरकर गांव-गांव बेचते हैं। सामान के पैसे जमा करते हैं। इस तरह से व्यापारियों के पास बहुत सारा पैसा और सोना-चांदी आभूषण आदि व्यापार संबंधित रहते हैं। अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए यह सब अनिवार्य है।व्यापारियों का कहना है कि देश में शादियों का मौसम शुरु होने वाला है। ऐसे समय माल की खपत बढ़ जाती है। ग्रामीण क्षेत्र से बहुत से लोग नगद पैसे लेकर शहर में खरीदी करने आते हैं। पैसे का चुनाव में दुरुपयोग ना हो यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है लेकिन अर्थव्यवस्था चलाने के लिए व्यापारियों को नगद, सोने चांदी के आभूषण आदि लेकर यात्रा करना भी जरुरी होता है। इसलिए व्यापार और व्यापारी को प्रभावित न करते हुए आचार संहिता का पालन होना चाहिए।

अगले हफ्ते आएगा प्रोसेसेड फूड बनाने वाली कंपनी का आईपीओ

नई दिल्ली ।

अगले हफ्ते 19 मार्च को प्रोसेस्ड फूड बनाने वाली कंपनी चडढा फूड का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। कंपनी का ये 34 करोड़ का आईपीओ बोली लगाने के लिए 21 मार्च तक खुला रहेगा। इस आईपीओ के तहत कंपनी के 59.62 लाख नए शेयर जारी किए जाएंगे। 21 मार्च को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होने के बाद इस कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 27 मार्च 2024 को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर हो सकती है। प्राइस बैंड की बात करें को इसके लिए 53 से 56 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज 2000 शेयरों का है। इश्यू के रिजर्व हिस्से की बात करें को इश्यू का 50 प्रतिशत हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, 35 प्रतिशत हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए और 15 प्रतिशत हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। आईपीओ के लिए इंडोरेंट फाइनेंशियाल सर्विसेज लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर है। साल 1999 में शुरू हुई ये कंपनी फ्रोजन और रेडी टू ईट प्रोसेस्ड मीड प्रोडक्ट बनाती है। इस एरिया में ये कंपनी भारत की दिग्गज कंपनियों में से एक है। कंपनी की वित्तिय स्थिति पर नजर डालें तो कंपनी का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2023 में 34.14 प्रतिशत बढ़कर 117.24 करोड़ रुपये और शुद्ध मुनाफा 264.66 प्रतिशत बढ़कर 2.45 करोड़ रुपये रहा।

कई राज्यों में और गिरे पेट्रोल-डीजल के भाव

- ब्रेंट क्रूड 85.34 डॉलर प्रति बैरल

नई दिल्ली ।

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट देखी जा रही है। रविवार को डब्ल्यूटीआई क्रूड बढ़कर 81.04 डॉलर प्रति बैरल पर बिक रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड 85.34 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। महाराष्ट्र में पेट्रोल 66 पैसे और डीजल 64 पैसे सस्ता हो गया है। पंजाब में पेट्रोल 30 और डीजल 34 पैसे सस्ता हो गया है। बिहार मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, और हिमाचल प्रदेश में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में गिरावट आई है। दूसरी और झारखण्ड और पश्चिम बंगाल समेत कुछ अन्य राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमत में तेजी दिख रही है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल 104.21 रुपये और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल 103.94 रुपये और डीजल 90.76 रुपये प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल 100.75 रुपये और डीजल 94.34 रुपये प्रति लीटर, नोएडा में पेट्रोल 94.71 रुपये और डीजल 87.81 रुपये प्रति लीटर हो गया है। गाजियाबाद में 94.65 रुपये और डीजल 87.75 रुपये प्रति लीटर हो गया है। लखनऊ में पेट्रोल 94.56 रुपये और डीजल 87.66 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पटना में पेट्रोल 105.24 रुपये और डीजल 92.10 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पोर्टब्लेयर में पेट्रोल 84.10 रुपये और डीजल 79.74 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

अमेरिकी कोर्ट से लगा बायजू को झटका, पैरेंट कंपनी पैसे हुए फ्रीज

मुंबई । संकट में फंसी एडटेक कंपनी बायजू की पैरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न को एक और झटका लगा। अमेरिकी कोर्ट ने कंपनी के 53.3 करोड़ डॉलर फीज कर दिए हैं। अमेरिकी कोर्ट ने आदेश में कहा है कि यह पैसा कहीं इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस फैसले को कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे कर्जदाताओं की जीत माना जा रहा है। थिंक एंड लर्न ने कानूनी विवादों में फंसने के बाद इस 53.3 करोड़ डॉलर को कथित तौर पर मॉर्टन हेज फंड में ट्रांसफर किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, कर्जदाताओं ने मांग की थी कि टेक फर्म द्वारा पैसे के इस्तेमाल को रोकने के लिए इस कोर्ट में जमा करवा दिया जाए। कोर्ट ने बायजू के फाउंडर बायजू रविंद्रन के भाई और कंपनी के डायरेक्टर रिजू रविंद्रन को निशाना बनाकर कहा कि आप बताइए पैसा कहां है। जज ने सुनवाई में कहा, मैं उनका विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि उन्हें पैसे के बारे में पता नहीं है। थिंक एंड लर्न उन्हें यह जानकारी क्यों नहीं दे रही कि पैसा कहां है। रवींद्रन के वकील शेरोन कोर्पस ने सुनवाई के दौरान अमेरिका कोर्ट में तर्क दिया कि थिंक एंड लर्न में चल रहे संकट के लिए कर्जदाता ही जिम्मेदार हैं। कर्जदाता ही हमारे ऊपर लोन डिफॉल्ट का जरूरत से ज्यादा दबाव बना रहे थे।

एफपीआई ने मार्च के पहले पखवाड़े में शेयरों में 40,710 करोड़ निवेश किया

नई दिल्ली । विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने इस महीने मार्च में के पहले पखवाड़े में भारतीय शेयर बाजारों में 40,710 करोड़ रुपये का निवेश किया है। वृहद आर्थिक परिदृश्य में सुधार और घरेलू मोर्चे पर मजबूत आंकड़ों से एफपीआई का भारतीय शेयरों में आकर्षण बना हुआ है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार इससे पहले फरवरी में एफपीआई ने शेयरों में 1,539 करोड़ रुपये डाले थे। वहीं जनवरी में उन्होंने 25,743 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे। बाजार के जानकार ने कहा कि एफपीआई अमेरिका में बॉन्ड प्रतिफल में बदलाव की वजह से अपनी रणनीति बदल रहे हैं। चूंकि अमेरिका में बॉन्ड पर प्रतिफल फिर बढ़ गया है, ऐसे में आगामी दिनों में एफपीआई फिर बिकवाली कर सकते हैं। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में सुधार की वजह से एफपीआई भारत जैसे बाजारों का रुख कर रहे हैं। इसके अलावा बाजार में हालिया करेक्शन से भी उन्हें निवेश का अवसर मिला है। शेयरों के अलावा एफपीआई ने समीक्षाधीन अवधि में ऋण या बॉन्ड बाजार में 10,383 करोड़ रुपये का निवेश किया है। ऋण या बॉन्ड बाजार की बात की जाए, तो ब्लूमबर्ग ने अगले साल 31 जनवरी से भारतीय बॉन्ड को इमर्जिंग मार्केट (ईएम) लोकल करेंसी गवर्नमेंट इंडेक्स में शामिल करने की घोषणा की है। इसके चलते एफपीआई बॉन्ड बाजार में पैसा लगा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बॉन्ड बाजार में फरवरी में 22,419 करोड़ रुपये, जनवरी में 19,836 करोड़ रुपये, दिसंबर में 18,302 करोड़ रुपये डाले थे। कुल मिलाकर इस साल अब तक एफपीआई भारतीय शेयर बाजार में 16,505 करोड़ रुपये डाल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ऋण बाजार में 52,639 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

अदाणी ग्रुप पर रिश्वतखोरी की आशंका में जांच जारी

मुंबई ।

अदाणी ग्रुप को लेकर जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। ब्लूमबर्ग के अनुसार अमेरिका अदाणी समूह के संस्थापक गौतम अदाणी और उनकी कंपनियों के रिश्वतखोरी में शामिल होने का आंशका पर जांच कर रही है। ब्लूमबर्ग ने मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाला से लिखा है कि जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या अदाणी समूह या गौतम अदाणी सहित कंपनी से जुड़े लोग, एक एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने में शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय और वाशिंगटन में न्याय विभाग की फॉड यूनिट इस जांच का काम संभाल रही है, और इस मामले में रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी एज्योर पावर ग्लोबल पर भी नजर रख रही है। इस मामले में अदाणी ग्रुप ने ब्लूमबर्ग को बताया कि हमें अपने चेयरमैन के खिलाफ किसी जांच की जानकारी नहीं है। एक कारोबारी व्यावसायिक समूह के रूप में हम भारत और अन्य देशों में भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वत विरोधी कानूनों के अधीन हैं और उनका पूरी तरह से पालन करते हैं। बता दें कि अदाणी समूह और एज्योर ग्रीन एनर्जी एरिया में दो बड़े खिलाड़ी हैं। बीते कुछ समय में दोनों ने एक ही राज्य-संचालित सौर कार्यक्रम के हिस्से के रूप में परियोजनाओं के लिए डील फाइनल की है। एज्योर, अवैध भुगतान की व्हिसलब्लोअर शिकायतों और देरी से की गई फाइलिंग के कारण पिछले साल के अंत में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया गया था। एज्योर ने पिछले साल कहा था कि वह न्याय विभाग और एसईसी के साथ सहयोग कर रहा है।

केंद्रीय बैंकों के नीतिगत फैसले शेयर बाजार को प्रभावित करेंगे

- रुपए की चाल, अमेरिकी ड पर प्रतिफल और कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव पर भी नजर रहेगी

मुंबई ।

रूस की तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के साथ ही अमेरिका में महंगाई की दर अनुमान से अधिक रहने के बाद फेड रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती शुरू करने को लेकर बढ़ी चिंता के दबाव में स्थानीय स्तर पर हुई भारी बिकवाली से बीते सप्ताह दो प्रतिशत की गिरावट देख चुके घरेलू शेयर बाजार पर इस सप्ताह` विश्व के कई केंद्रीय बैंकों की नीतिगत दरों को लेकर होने वाली बैठकों के निर्णय का असर रहेगा। इसके अलावा वैश्विक बाजारों का रुख और विदेशी निवेशकों की गतिविधियां भी बाजार के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। विश्लेषकों ने यह राय जताई है। पिछले सप्ताह छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट, विदेशी कोषों की निकासी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि सप्ताह के दौरान दुनिया के कई केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति पर अपने रुख की घोषणा करेंगे। ऐसे में निकट अवधि में शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव रह सकता है। बाजार के जानकारों ने कहा कि इस सप्ताह मौद्रिक नीति पर सभी का ध्यान रहेगा। फेडरल रिजर्व की दो दिन की नीतिगत बैठक 19 मार्च को शुरू होने जा रही है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक 20 मार्च को ब्याज दरों पर अपने निर्णय की घोषणा करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा चीन एक साल और पांच साल के कर्ज पर प्रमुख दरों की घोषणा करेगा। बैंक ऑफ जापान (बीओजे) 19 मार्च को ब्याज दर पर अपने निर्णय की घोषणा करेगा। जापान 22 मार्च को ही मुद्रास्फीति के आंकड़े भी जारी करेगा। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल, अमेरिकी बॉन्ड पर प्रतिफल और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर सभी की नजर रहेगी। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि अनिश्चितता के बीच निवेशक शेयरों में अपने निवेश के लिए वैश्विक बाजारों के रुख पर निगाह रखेंगे। उन्होंने कहा कि यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। वैश्विक स्तर पर कई बड़े केंद्रीय बैंक अपनी नीतिगत रुख की घोषणा करेंगे। ऐसे में हमारा मानना है कि निकट अवधि में बाजार में अस्थिरता रहेगी। निवेशकों का ध्यान बड़े और सुरक्षित शेयरों पर रहेगा। विश्लेषकों का कहना है कि निवेशकों का ध्यान अब आगामी लोकसभा चुनावों पर रहेगा। सात चरणों के लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। मतों की गिनती चार जून को होगी। आने वाले सप्ताह में वैश्विक केंद्रीय बैंकों के मौद्रिक नीति निर्णय पर निवेशकों का ध्यान रहेगा। फेडरल रिजर्व के साथ बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड सप्ताह के दौरान ब्याज दरों पर अपने निर्णय की घोषणा करेंगे।

हिमालय क्षेत्र में विदेशी फसलों की खेती को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली । विश्व सहकारी आर्थिक मंच हिमालय क्षेत्र में विदेशी बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए आईसीएआर-केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान सहित कई संगठनों के साथ मिलकर काम करेगा। इस मंच की स्थापना भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए की गई है। विश्व सहकारी आर्थिक मंच ने एक बयान में कहा कि वह भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई), आईसीएआर-केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान (सीआईटीएच), कंफेडरेशन ऑफ एनजीओ ऑफ रूरल इंडिया (सीएनआरआई) और शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (एसकेयूएएसटी) सहित विभिन्न संस्थानों के साथ सहयोग करेगा। बयान के मुताबिक शुरुआत में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में हेजलनट, अखरोट और अन्य विदेशी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये संस्थान इन फसलों की खेती को बढ़ावा देने के अलावा कौशल प्रशिक्षण देंगे और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में युवाओं को बताएंगे।

सरसों तेल तिलहन की कीमतें गिरावट के साथ बंद

- मांग कमजोर रहने से बिनौला तेल की कीमतें भी पूर्ववत बंद हुई

नई दिल्ली ।

होली की छुट्टियों से पहले थोक मंडियों में रिकॉर्ड आवक होने से शनिवार को सरसों तेल तिलहन कीमतें गिरावट के साथ बंद हुई। दूसरी ओर खाद्य तेलों की आपूर्ति कम रहने के बीच सोयाबीन तेल तिलहन, कच्चा पामतेल (सीपीओ) एवं पामोलीन के दाम मजबूत रहे। मूंगफली तेल तिलहन और बिनौलातेल के भाव पूर्वस्तर पर बंद हुए। बाजार सूत्रों ने कहा` कि होली की लंबी छुट्टी से पहले विशेषकर छोटे किसान अपनी ऊपज बाजार में ला रहे हैं और इसकी आवक सवा चार लाख बोरी से बढ़कर लगभग 4.50 लाख बोरी हो गई। आवक बढ़ने के साथ साथ सरसों का दाम तोड़ने के लिए कुछ निहित स्वार्थी तत्व यह चर्चा भी फैलाने में लगे हैं कि अगले महीने सोयाबीन डीगम और सूरजमुखी तेल का आयात बढ़ने वाला है। सूत्रों ने कहा कि ऊंचे दाम पर मांग कमजोर रहने के बीच मूंगफली तेल तिलहन के पूर्वस्तर पर रहने के अलावा बिनौला तेल कीमतें भी पूर्ववत बंद हुई।तेल-तिलहनों के भाव इस प्रकार रहे= सरसों तिलहन- 5,425-5,465 रुपये प्रति क्विंटल, मूंगफली - 6,125-6,400 रुपये प्रति क्विंटल, मूंगफली तेल मिल डिलिवरी (गुजरात) - 15,000 रुपये प्रति क्विंटल, गफली रिफाइंड तेल 2,250-2,525 रुपये प्रति टिन, सरसों तेल दादरी- 10,350 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों पक्की घानी- 1,750-1,850 रुपये प्रति टिन, सरसों कच्ची घानी- 1,750 -1,855 रुपये प्रति टिन, तिल तेल मिल डिलिवरी - 18,900-21,000 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन तेल मिल डिलिवरी दिल्ली- 11,200 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन मिल डिलिवरी इंदौर- 10,900 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन तेल डीगम, कांडला-9,650 रुपये प्रति क्विंटल, सीपीओ एक्स-कांडला- 9,225 रुपये प्रति क्विंटल, बिनौला मिल डिलिवरी (हरियाणा)- 9,600 रुपये प्रति क्विंटल, पामोलिन आरबीडी, दिल्ली- 10,650 रुपये प्रति क्विंटल, पामोलिन एक्स- कांडला-9,750 रुपये (बिना जीएसटी के) प्रति क्विंटल, सोयाबीन दाना - 4,645-4,665 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन लूज- 4,445-4,485 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का खल (सरिस्का)- 4,075 रुपये प्रति क्विंटल।

ट्रेडिंग को बेहतर और आसान बनाने वाले उपायों को सेबी की मंजूरी

मुंबई ।

शेयर बाजार नियामक, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को और बेहतर व आसान बनाने के कई उपायों को मंजूरी दे दी है। इन उपायों में ऑप्शनल टी+0 सेटलमेंट के बीटा संस्करण के लांच को मंजूरी और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और प्रारंभिक शेयर बिक्री के माध्यम से धन जुटाने की चाहत रखने वाली इकाइयों को छूट प्रदान करना शामिल है। सेबी बोर्ड ने बैठक के दौरान प्रस्तावों को मंजूरी दी। सेबी ने बयान में कहा कि इक्विटी शेयर के सार्वजनिक/राइट्स इश्यू में एक प्रतिशत 'सिक्योरिटी डिपॉजिट' की आवश्यकता को खत्म करने और अप्रत्याशित घटना के कारण ऑफर समापन तिथि के विस्तार को लचीलापन बनाने का निर्णय हुआ है। सेबी ने कहा, हितधारकों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने 25 शेयरों के सीमित सेट और दलालों के सीमित सेट के साथ वैकल्पिक टी+0 निपटान के बीटा संस्करण को लांच करने की मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी मार्केट में अब तक टी+1 सेटलमेंट साइकल पर काम होता आया है। टी+1 सेटलमेंट को 2021 में पेश किया गया था और चरणों में लागू किया गया, अंतिम चरण जनवरी 2023 में पूरा हुआ। अब टी+0 के आने से शेयर की खरीदारी और बिक्री का सेटलमेंट एक ही दिन में होगा।

पिछले एक साल में भारतीय पेटेंट कार्यालय ने एक लाख पेटेंट दिए

नई दिल्ली । भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पिछले एक साल में एक लाख से अधिक पेटेंट दिए हैं। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार के उपायों के चलते ये नतीजे आए। बयान के मुताबिक इस दौरान भौगोलिक संकेत (जीआई) पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो इससे पिछले साल की तुलना में तीन गुना है। इस समय भारत में 573 जीआई पंजीकृत हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में 98 नए जीआई पंजीकृत किए गए और 31 मार्च तक 62 अन्य को पंजीकृत किए जाने की उम्मीद है। इसी तरह चालू वित्त वर्ष में अब तक कॉपीराइट और डिजाइन पंजीकरण के आंकड़े क्रमश= 36,378 और 27,819 हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बयान में कहा` कि पेटेंट कार्यालय ने पिछले एक साल (15 मार्च 2023 से 14 मार्च 2024) में एक लाख से अधिक पेटेंट दिए हैं। प्रत्येक कार्य दिवस में करीब 250 पेटेंट दिए गए। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने पेटेंट हासिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पेटेंट नियम, 2024 में कई प्रावधान किए हैं।